

[2023] 10 एस. सी. आर 993:2023 आई. एन. एस. सी 603

ए.

यू. पी. राज्य बनाम

सोनू कुशवाह

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 1633) 05 जुलाई, 2023

बी.

[अभय एस. ओका और राजेश बिंदल, जे. जे.]

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012:एसएस।6, 5 खंड (एम)-गंभीर भेदक यौन हमला-अभियोजन मामले के लिए सजा कि आरोपी ने लगभग 10 साल की उम्र में पीड़ित के मुंह में अपना लिंग डाल दिया था और वीर्य छोड़ दिया था-दोषसिद्धि यू/एस।377 और 506 आई. पी. सी. और एस.5 आर/डब्ल्यू एस।6 पॉक्सो अधिनियम के तहत, और तदनुसार सजा सुनाई गई-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने माना कि अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य दंडनीय यौन हमले का था।⁴ और सजा को कम कर दिया-की शुद्धता-आयोजित:अभियुक्त ने गंभीर भेदक यौन हमले का अपराध किया है क्योंकि उसने बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर भेदक यौन हमला किया है।⁵, जो कोई भी बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर भेदक यौन हमला करता है, गंभीर भेदक यौन हमला करने का दोषी है, वह आकर्षित होता है-इसके अलावा, हालांकि कानून न्यूनतम सजा का प्रावधान करता है, आरोपी द्वारा किया गया अपराध बहुत ही वीभत्स है जो बहुत सख्त सजा की मांग करता है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को अपास्त करना दिया जाता है और निचली विचारण न्यायालय के फैसले को बहाल कर दिया जाता है।

सी.

डी.

ई.

आयोजित होने का दायरा और परिधि:विभिन्न प्रकार के बाल शोषण के अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड प्रदान करने के लिए पॉक्सो अधिनियम लागू किया गया था-इसलिए, एस. एस. में न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं।⁴, ⁶, ⁸ और ¹⁰ बच्चों पर यौन हमलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए -धारा 6 अपनी सरल भाषा में, न्यायालय के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ती है और न्यूनतम सजा-एस. एस. अधिरोपित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।⁴, ⁶, ⁸ और ¹⁰.

एफ.

जी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** प्रत्यर्थी ने गंभीर भेदक यौन हमले का अपराध किया है क्योंकि उसने बारह साल से कम उम्र के बच्चे पर भेदक यौन हमला किया है। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण की धारा **5** का खंड (एम) ए

एच.

993

994 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

अधिनियम, **2012** तत्काल मामले में आकर्षित किया जाता है। अपराध करने की तारीख को, गंभीर भेदक यौन हमले के लिए दस साल के लिए सश्रम कारावास न्यूनतम सजा निर्धारित की गई थी। **16** अगस्त **2019** से न्यूनतम सजा को बढ़ाकर बीस साल कर दिया गया है। हालाँकि, संशोधित प्रावधान इस मामले पर लागू नहीं होगा क्योंकि यह घटना **16** अगस्त **2019** से पहले हुई है। [पारस **9** और **10**] [999-ए-डी]

बी.

1.2 उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा **5** लागू नहीं थी, और प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अपराध भेदक यौन हमले के कम अपराध की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय है। **4** पॉक्सो अधिनियम। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए एक त्रुटि की कि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया कार्य एक गंभीर भेदक यौन हमला नहीं था। वास्तव में, विशेष न्यायालय प्रत्यर्थी यू/को दंडित करने में सही था एस. **6** और उसे **5,000/-** रुपये के जुर्माने के साथ दस साल के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई। [पैरा **11**] [999-ई-एफ]

सी.

डी.

1.3 पॉक्सो अधिनियम विभिन्न प्रकार के बाल शोषण के अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था और यही कारण है कि बच्चों पर यौन हमलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा **4, 6, 8** और **10** में न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं। इसलिए, धारा **6**, अपनी सरल भाषा में, न्यायालय के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ती है और निचली विचारण न्यायालय द्वारा दी गई न्यूनतम सजा को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब कोई दंडात्मक प्रावधान वाक्यांश का उपयोग करता है तो "इससे कम नहीं होगा।", न्यायालय धारा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और कम सजा नहीं दे सकते हैं। न्यायालयें ऐसा करने के लिए शक्तिहीन हैं जब तक कि कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं है जो न्यायालय को कम सजा देने में सक्षम बनाता है। हालांकि, पॉक्सो अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्यर्थी उच्च

न्यायालय द्वारा संशोधित सजा से गुजरने के बाद जीवन में आगे बढ़ गया होगा, उसके प्रति कोई नरमी दिखाने का कोई सवाल ही नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि कानून न्यूनतम सजा का प्रावधान करता है, प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अपराध बहुत वीभत्स है जिसमें बहुत कड़ी सजा की आवश्यकता होती है। पीड़ित-बच्चे के दिमाग पर अप्रिय कृत्य का प्रभाव ए होगा

ई.

एफ.

जी.

एच.

995

यू. पी. राज्य बनाम सोनू कुशवाह ए

जीवन भर रहें। प्रभाव पीड़ित के स्वस्थ विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए बाध्य है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि घटना के समय पीड़ित की उम्र बारह वर्ष से कम थी। इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को अपास्त करवाने और निचली विचारण न्यायालय के फैसले को बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अपास्त करना कर दिया जाता है और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दस साल के सश्रम कारावास से गुजरना होगा और **5,000/-** रुपये का जुर्माना देना होगा। [पारस **12** और **13**]

[1000-ए-सी; डी-ई]

बी.

सी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: 2023 की आपराधिक अपील No.1633।

2018 के सी. आर. एल. ए. सं. 5415 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

कृष्णानंद पांडे, हरह प्रताप शाही, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

डी.

सतीश पांडे, अब्दुल कादिर, अकबर अली, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस. ओका, जे. फैक्टुअल एस्पेक्ट्स

ई.

1. इस अपील में शामिल एकमात्र सवाल यह है कि क्या प्रत्यर्थी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में, 'पॉक्सो अधिनियम') की धारा 6 के तहत दंडनीय गंभीर भेदक यौन हमले के अपराध का दोषी है।

एफ.

2. प्रत्यर्थी -अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप विद्वान , आई. पी. सी.) की धारा 377 और 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 सहपठित धारा 5 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। झांसी के 8 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जो पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश थे, ने प्रत्यर्थी को तीनों अपराधों के लिए दोषी ठहराया। प्रत्यर्थी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी और उसे 5,000 रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया था। प्रत्यर्थी को सात के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी

जी.

एच.

996

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

आई. पी. सी. की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध के लिए वर्ष। आई. पी. सी. की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उन्हें एक साल के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। अंतिम दो अपराधों के लिए जुर्माना भी लगाया गया था।

3. प्रत्यर्थी ने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की आपराधिक अपील No.5415 को प्राथमिकता दी। विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय भेदक यौन हमले के अपराध का दोषी था न कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय गंभीर भेदक यौन हमले का अपराध। इसलिए, पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए उनकी मूल सजा को 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल के कारावास में लाया गया। केवल इस हद तक, अपील की अनुमति दी गई थी।

बी.

सी.

4. यह विवादित नहीं है कि अपराध के समय पीड़ित की आयु बारह वर्ष से कम थी। उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले के पैराग्राफ 3 में मामले के तथ्यों का सारांश दिया गया है, जो इस प्रकार है:

डी.

“3. संक्षेप में कहें तो अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि शिकायतकर्ता XYZ ने अपीलार्थी सोनू कुशवाहा के खिलाफ जिला झांसी के चिरगांव में 26.03.2016 पर एक एफ. आई. आर. दर्ज की, जिसमें कहा गया है कि 22.03.2016 पर लगभग 05 बजे:00 शाम को अपीलार्थी सोनू कुशवाहा शिकायतकर्ता के घर आए और अपने लगभग 10 साल के बेटे को हरदौल के मंदिर में ले गए। वहाँ अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता के बेटे यानी पीड़ित को Rs.20 दिया और उसका लिंग चूसने के लिए कहा। अपीलार्थी सोनू कुशवाहा ने अपना लिंग पीड़ित के मुँह में डाल दिया। इसके बाद, पीड़ित उस Rs.20 के साथ घर आया। इस पर, शिकायतकर्ता के भतीजे संतोष ने पीड़ित से पूछा कि उसे Rs.20 कहाँ से मिला, फिर पीड़ित ने बताया कि पूरी घटना उसके साथ हुई थी। अपीलार्थी ने पीड़ित को घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी।”

ई.

एफ.

पैराग्राफ 16 में, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए हैं। पैराग्राफ 16 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

जी.

“16. मामले के सिद्ध तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी ने लगभग 10 वर्ष की आयु के पीड़ित के मुँह में अपना लिंग डाल दिया और उसमें वीर्य छोड़ दिया।.....”

एच.

997

यू. पी. राज्य बनाम सोनू कुशवाहा [अभय एस. ओका, जे.] ए.

ए.

प्रतिवादी-अभियुक्त द्वारा इस निष्कर्ष पर हमला नहीं किया गया है क्योंकि उसने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी थी। उक्त निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष

निकाला कि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया कार्य भेदक यौन हमले का था जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय था।

प्रस्तुतियाँ

बी.

5. अपीलार्थी-राज्य उत्तर प्रदेश की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 के खंड (ए) के तहत 'भेदक यौन हमले' की परिभाषा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि धारा 5 के खंड (एम) के तहत, जो कोई भी बारह साल से कम उम्र के बच्चे पर भेदक यौन हमला करता है, वह गंभीर भेदक यौन हमले का दोषी है। इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके एक त्रुटि की है कि धारा 6, जो गंभीर भेदक यौन हमले पर लागू होती है, लागू नहीं थी।

सी.

6. प्रत्यर्थी -अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी पहले ही सात साल की सजा काट चुका है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अब प्रत्यर्थी में पूरी तरह से सुधार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्यर्थी जीवन में आगे बढ़ गया है और वास्तव में, हाल ही में उसने शादी की है। इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि इस स्तर पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 को लागू करना और प्रत्यर्थी को आगे की सजा भुगतने के लिए जेल भेजना अन्यायपूर्ण होगा।

डी.

ई.

हमारा दृष्टिकोण

7. उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के पैराग्राफ 16 में दर्ज निष्कर्ष की शुद्धता के बारे में कोई विवाद नहीं है, जिसे हमने ऊपर उद्धृत किया है। इस संदर्भ में, पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 में शामिल 'भेदक यौन हमले' की परिभाषा पर ध्यान देना आवश्यक है। धारा 3 का खंड (ए) इस प्रकार है:

एफ.

“3. भेदक यौन हमला।- एक व्यक्ति को प्रतिबद्ध कहा जाता है

“भेदक यौन हमला "यदि -

जी.

(क) वह अपने लिंग को किसी भी हद तक बच्चे की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है या बच्चे को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है; या

(बी)।

एच.

998

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

(ग) (घ) "।

8. पॉक्सो अधिनियम की धारा 2 (ए) में प्रावधान है कि 'उग्र भेदक यौन हमले' का वही अर्थ है जो धारा 5 में दिया गया है। इसलिए, हम धारा 5 पर आते हैं, जो 'उग्र भेदक यौन हमले' को परिभाषित करती है। धारा 5 का खंड (एम) इस प्रकार है:

बी.

"5. उग्र भेदक यौन हमला।-

(ए). (बी). (सी). (डी). (ई). (एफ). (जी). (एच). (आई). (जे). (के). (एल)।

सी.

डी.

ई.

(एम) जो कोई भी बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर भेदक यौन हमला करता है; या

एफ.

(एन). (ओ). (पी). (क्यू). (आर). (एस). (टी)।

जी.

(यू)., को उग्र भेदक यौन हमला करने के लिए कहा जाता है "

एच.

999

यू. पी. राज्य बनाम सोनू कुशवाह [अभय एस. ओका, जे.] ए.

ए.

9. विवादित फैसले के पैराग्राफ 16 में दर्ज निष्कर्ष पर विचार करते हुए, जाहिर है कि इस मामले में, प्रत्यर्थी ने गंभीर भेदक यौन हमले का अपराध किया है क्योंकि उसने बारह साल से कम उम्र के बच्चे पर भेदक यौन हमले किए हैं। इस मामले में धारा 5 का खंड (एम) आकर्षित किया गया है।

10. धारा 6, जैसा कि 16 अगस्त 2019 को इसके प्रतिस्थापन से पहले लागू था, इस प्रकार पढ़िए:

बी.

“6. बड़े हुए भेदक यौन हमले के लिए सजा।—

जो कोई भी गंभीर भेदक यौन हमला करता है, उसे एक ऐसी अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी जो दस साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी।”

सी.

अपराध करने की तारीख को, गंभीर भेदक यौन हमले के अपराध के लिए दस साल के लिए सश्रम कारावास न्यूनतम सजा निर्धारित की गई थी। 16 अगस्त 2019 से न्यूनतम सजा को बढ़ाकर बीस साल कर दिया गया है। हालाँकि, संशोधित प्रावधान इस मामले पर लागू नहीं होगा क्योंकि यह घटना 16 अगस्त 2019 से पहले हुई है।

डी.

11. आश्चर्यजनक रूप से, उच्च न्यायालय ने कहा है कि धारा 5 लागू नहीं थी, और प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अपराध भेदक यौन हमले के कम अपराध की श्रेणी में आता है, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके एक स्पष्ट त्रुटि की कि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया कार्य एक गंभीर भेदक यौन हमला नहीं था। वास्तव में, विशेष न्यायालय ने प्रत्यर्थी को धारा 6 के तहत दंडित करने और उसे 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ दस साल के सश्रम कारावास की सजा देने में सही था।

ई.

एफ.

12. पॉक्सो अधिनियम विभिन्न प्रकार के बाल शोषण के अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था और यही कारण है कि बच्चों पर यौन हमलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 और 10 में न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं। इसलिए, धारा 6, अपनी सरल भाषा में, न्यायालय के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ती है और विचारण न्यायालय द्वारा दी गई न्यूनतम सजा को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब कोई दंडात्मक प्रावधान वाक्यांश का उपयोग करता है तो "इससे कम नहीं

होगा।”, न्यायालय धारा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और कम सजा नहीं दे सकते हैं। न्यायालय ऐसा करने के लिए शक्तिहीन हैं जब तक कि कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं है जो न्यायालय को एक

जी.

एच.

1000

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

कम वाक्य।हालाँकि, हमें पॉक्सो अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिलता है। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित सजा से गुजरने के बाद जीवन में आगे बढ़ गया होगा, उसके प्रति कोई नरमी दिखाने का कोई सवाल ही नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि कानून न्यूनतम सजा का प्रावधान करता है, प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अपराध बहुत वीभत्स है जिसमें बहुत कड़ी सजा की आवश्यकता होती है। पीड़ित-बच्चे के दिमाग पर अप्रिय कृत्य का प्रभाव जीवन भर रहेगा। प्रभाव पीड़ित के स्वस्थ विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए बाध्य है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि घटना के समय पीड़ित की उम्र बारह वर्ष से कम थी। इसलिए, हमारे पास उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को अपास्त करवाने और विचारण न्यायालय के फैसले को बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

बी.

सी.

13. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2018 की आपराधिक अपील में 18 नवंबर 2021 को पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश अपास्त करना कर दिया गया है और 24 अगस्त 2018 को विद्वान 8 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, झांसी द्वारा 2016 के विशेष सत्र परीक्षण में पारित किए गए फैसले और आदेश को बहाल कर दिया गया है। तदनुसार, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर 2018 की आपराधिक अपील No.5415 खारिज हो जाती है। प्रत्यर्थी पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दस साल के लिए सश्रम कारावास से गुजरेगा और 5,000/- रुपये का जुर्माना चुकाएगा। हम प्रत्यर्थी को अधिकतम एक महीने की अवधि के भीतर पॉक्सो अधिनियम, झांसी के तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हैं। उसके आत्मसमर्पण करने पर, विशेष न्यायालय प्रत्यर्थी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शेष सजा काटने के लिए जेल भेजेगा। आज से एक महीने के भीतर प्रत्यर्थी के आत्मसमर्पण करने में विफल रहने पर,

विशेष न्यायालय प्रत्यर्थी के खिलाफ तुरंत गैर-जमानती वारंट जारी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्यर्थी पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शेष सजा काटने के लिए जेल जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस फैसले की एक प्रति तुरंत विशेष अदालत को भेजी जाएगी।

डी.

ई.

एफ.

जी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: वरुण धोंड, एलसीआरए)

एच.